



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2011/ज्येष्ठ 27, 1933

No. 124]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011/JYAISTHA 27, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

(निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 17 जून, 2011

विषय : चीन जन गण के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम फार्मेलिडहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच ।

सं. 15/16/2009-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उस पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

2. यतः उपर्युक्त नियम को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन गण के मूल या वहाँ से निर्यातित सोडियम फार्मेलिडहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) के आरपित पाटन की 28 जनवरी, 2005 को पाटनरोधी जांच शुरू की और प्राधिकारी के 26 अगस्त, 2005 के प्रारम्भिक जांच परिणामों के आधार चीन जन गण से सोडियम फार्मेलिडहाइड सल्फोक्सिलेट के आयातों पर 11 नवम्बर, 2005 की सी.शु. अधिसूचना सं. 95/2005-सी.शु. के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । अंतिम जांच परिणाम 25 जनवरी, 2006 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग ने 6 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. 23/2006-सी.शु. के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

3. और यतः अधिनियम और नियम में प्राधिकारी के लिए पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना अपेक्षित है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2006 कर डब्ल्यू पी सं. 16/893 में यह निर्णय दिया था कि इस बात के निर्धारण हेतु निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है कि क्या मौजूदा शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः प्राधिकारी ने लागू शुल्क को सतत रूप से जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए पाटनरोधी नियम के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार 22 जून, 2010 की अधिसूचना के तहत निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी ।

4. और यतः 6 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं० 23/2006-सी.शु. के तहत अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क की अवधि अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार 1 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना सं० 114/2010-सी.शु. के तहत 21 जून, 2011 तक बढ़ाई गई थी।

ख. सामान्य प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 22 जून, 2010 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत चीन जन गण के उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में सोडियम फार्मेलिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) के पाटन के खिलाफ लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसकी राशि में वृद्धि करने हेतु ट्रांसपैक-सिलोक्स इंडस्ट्री लि० द्वारा दायर, डेमोसो केमिकल्स प्रा० लि० द्वारा समर्थित एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादक और/अथवा निर्यातकों को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर संगत सूचना उपलब्ध कराने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(iii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के समस्त ज्ञात आयातकों और/अथवा उपभोक्ताओं को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर संगत सूचना उपलब्ध कराने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रतियां उपलब्ध कराईं। अनुरोध किए जाने पर अगोपनीय आवेदन की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।

(v) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों सहित संबद्ध देश की सरकार को संगत सूचना मांगने के लिए प्रश्नावली भेजी। तथापि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

(vi) नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए ज्ञात आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में जांच के लिए संगत मानी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं को अवसर प्रदान किया।

(vii) संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने हेतु 18 जनवरी, 2011 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें ट्रांसपैक-सिलोक्स इंडस्ट्री लि०, डेमोसा केमिकल्स प्रा० लि० और टी पी एम कंसलटेंट्स (ट्रांसपैक-सिलोक्स इंडस्ट्री लि० के परामर्शदाता) ने भाग लिया था। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना के लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त इन लिखित अनुरोधों पर विचार किया है। तथापि किसी भी उत्पादक/निर्यातक अथवा आयातक ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया और इसलिए उन्होंने लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध पक्षकारों को एक और अवसर प्रदान करने के लिए 30 मार्च, 2011 को एक अन्य सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। यह नोट किया जाता है कि इस दूसरी सुनवाई में भी घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया। जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों तथा प्रदत्त सूचना/साक्ष्य पर उस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा समुचित विचार किया गया है जिस सीमा तक उन्हें वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।

(viii) जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों और प्रदत्त सूचना/साक्ष्य पर प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में उस सीमा तक समुचित विचार किया जाएगा जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।

(ix) जांच के दौरान प्राधिकारी ने प्रदत्त उस सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया जिस पर यह जांच परिणाम आधारित है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया। क्षति के बारे में घरेलू उद्योग से अतिरिक्त/पूरक ब्यौरे मांगे गए थे जो प्राप्त भी हो गए थे।

(x) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच परिणाम के लिए विचारित आवश्यक तथ्य/आधार का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(xi) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराया और नियम 6(7) के अनुसार उसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।

(xii) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत निकाली गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xiii) *** यह चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर उसे गोपनीय ही माना है।

(xiv) यह जांच 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि (12 माह और जिसका उल्लेख जांच अवधि के रूप में किया गया है) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 की अवधि और जांच अवधि शामिल है।

(xv) जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है वहाँ प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज करेंगे।

(xvi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारियों ने अपेक्षानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण (जिसे वर्तमान जांच में संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम फार्मेलिहाइड सल्फोक्सिलेट (जिसे वर्तमान जांच में एस एफ एस या संबद्ध वस्तु कहा गया है) है।

घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(i) वर्तमान जांच चीन जन गण के उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में सोडियम फार्मेलिहाइड सल्फोक्सिलेट के पाटन के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी राशि में वृद्धि करने और उसे जारी रखने के बारे में है।

(ii) समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही रहना चाहिए जैसा कि मूल जांच में माना गया है।

(iii) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम फार्मेलिहाइड सल्फोक्सिलेट है। मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में नाम, फार्मूला, विवरण, ग्रेड, उपयोग, पैकिंग, परिवहन, वर्गीकरण, हैंडलिंग आदि सहित उत्पाद के पूर्ण विवरण की जांच की जा चुकी है और संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकॉर्ड में है।

(iv) सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) का प्रमुख उपयोग वस्त्र छपाई में एक सशक्त डिस्चार्जिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सफेद डिस्चार्जिंग एजेंट या रंगीन डिस्चार्जिंग एजेंट के रूप में भी किया जा सकता है। रबड़ उद्योग में इसका उपयोग स्टाइरिन-बुटाडिन रबड़ के उत्पादन में एक्टिवेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य, पॉलिमर, भेषज और विविध उद्योगों में भी किया जाता है।

(v) चीन जन गण से निर्यातित सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) और याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन गण से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। दोनों उत्पादों में भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य तथा उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के संबंध में तुलनीय विशेषताएं हैं।

(vi) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तु है।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु तथा वर्तमान जांच के क्षेत्र के बारे में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण (जिसे वर्तमान जांच में संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट (जिसे वर्तमान जांच में एस एफ एस या संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि मूल जांच में माना गया है।

10. सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष सं० 28311020 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया था:-

पूर्ववर्ती जांचों और वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) है। यह सफेद चिप्स, पाउडर, हल्की विशिष्ट गंध से युक्त

छोटे दानों के रूप में एक अकार्बनिक रसायन है। एस एफ एस का उत्पादन जिक डस्ट, जल एवं सल्फर डायऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। उत्पाद के विभिन्न रूपों में कोई खास अंतर नहीं है। अलग-अलग रूपों का उत्पादन ग्राहक के अंतिम अनुप्रयोग की जरूरत पर निर्भर करता है और अलग-अलग रूप समान प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। सोडियम फार्मेलिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) का प्रमुख उपयोग वस्त्र छपाई में एक सशक्त डिस्चार्जिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सफेद डिस्चार्जिंग एजेंट या रंगीन डिस्चार्जिंग एजेंट के रूप में भी किया जा सकता है। रबड़ उद्योग में इसका उपयोग स्टाइरिन-बुटाडिन रबड़ के उत्पादन में एक्टिवेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य, पॉलिमर, भेषज और विविध उद्योगों में भी किया जाता है।

12. रिकॉर्ड तथा जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को पहले के समान रखना ही उचित समझते हैं। अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को सोडियम फार्मेलिहाइड सल्फोक्सिलेट (एस एफ एस) के रूप में परिभाषित किया है।

13. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश से उत्पादित और/अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान माना जा सकता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने इस मुद्दे की जांच की है और प्राधिकारी के पूर्ववर्ती निर्धारण का विरोध करते हुए उसे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। जांच के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित या वहाँ उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(i) वर्तमान याचिका मै0 ट्रांसपैक-सिलोक्स इंडस्ट्री लि0 ने दायर की थी जिसका समर्थन मै0 डेमोसा केमिकल्स प्रा0 लि0 ने किया था। जहाँ तक टी सी पी लि0 द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन का संबंध है याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उक्त कंपनी ने क्षति अवधि के दौरान नगण्य उत्पादन किया है।

(ii) याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक बनता है। (वस्तुतः यह भारतीय उत्पादन का लगभग 65.6 प्रतिशत था।) अतः याचिकाकर्ता का उत्पादन "कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग" बनता है।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. इस संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. नियम 2 (ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे सभी घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु का विनिर्माण करते हैं अथवा उससे जुड़ा कोई कार्यकलाप करते हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है सिवाय इस बात के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा वे स्वयं उसके आयातक हों ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के रूप में ही निकाला जाएगा।

17. याचिकाकर्ता कंपनी के उत्पादन का भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। इसके अलावा याचिका का समर्थन मै0 डेमोसा केमिकल्स प्रा0 लि0 ने किया है। अतः याचिका को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया माना गया है।

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार याचिकाकर्ता और समर्थकों का उत्पादन भारतीय उत्पादनों का एक बड़ा भाग है और वे नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

ड. अन्य मुद्दे

घरेलू उद्योग के विचार

19. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :-

(i) याचिका हर तरह से पूर्ण है तथा पिछली जांच संबंधी शुरुआत के बाद प्राधिकारी को पर्याप्त तथा सही साक्ष्य प्रदान किया गया था।

(ii) प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। अतः निर्यातकों को नियम 6(8) के अनुसार असहयोगी माना जाना चाहिए और प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

(iii) यह सूचना दी गई है कि भारत में सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट का निर्यात वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में चीन, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी और रूस से तथा 2008-09 में ईरान से हुआ है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि भारत और चीन के अलावा केवल दो ऐसे देश हैं जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण की सुविधा स्थापित की है और ये देश हैं -

यूरोप और ताइवान । अतः थाईलैंड, इंडोनेशिया और रूस से भारत को किए गए आयात मात्र यानांतरण का मामला बनता है क्योंकि इन देशों में विनिर्माण सुविधाओं का अभाव है ।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. वर्तमान जांच के संबंध में संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार के अनुरोधों को नोट किया है और इन मुद्दों पर नियमानुसार इस अंतिम जांच परिणाम में समुचित शीर्षों में विचार किया गया है ।

पाटन तथा पाटन मार्जिन की गणना

अ. पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:-

(i) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए । बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के बारे में चीन के किसी उत्पादक/निर्यातक ने कोई दावा नहीं किया है । चीन के निर्यातक ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा किया है । ऐसा मामला होने के कारण अनुबंध-1 के पैरा 8 को लागू करने और इस बात पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता कि क्या चीन की कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था की हकदार हैं ।

(ii) मूल जांच में प्राधिकारी ने चीन के किसी प्रतिवादी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया है ।

(iii) अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने यूरोप को एक उचित प्रतिनिधि देश माना है । प्राधिकारी यूरोप को एक उचित प्रतिनिधि देश मानने पर विचार करें । विकल्पतः प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भारत को एक उचित देश मान सकते हैं ।

(iv) वर्तमान जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में जहां कोई सतत आयात न हुआ हो निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालेंगे कि कोई सतत पाटन नहीं हुआ है तथापि जांच अवधि में सतत आयात न होने का तात्पर्य यह नहीं है कि

पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की जरूरत है। इसका तात्पर्य मात्र यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारण करें कि क्या पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने अन्य देशों के व्यवहारों का भी उल्लेख किया है जहां जांच अवधि में कोई निर्यात न होने के बावजूद पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाई गई है।

(v) पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना की पुष्टि निम्नलिखित से की जाती है:-

- (क) यद्यपि जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ था तथापि उक्त अवधि में निर्यात हुए हैं। याचिकाकर्ता ने इन निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित किया है और यह दावा किया है कि ये निर्यात अत्यधिक पाटित कीमतों पर हुए हैं।
- (ख) जांच अवधि के बाद उत्पाद का निर्यात हुआ है। ये निर्यात भी अत्यधिक पाटित कीमतों पर हुए थे।
- (ग) चीन से तीसरे देश को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात अत्यधिक पाटित कीमत पर हुआ है।
- (घ) उस कीमत पर विचार करते हुए जिस कीमत पर चीन के उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान और जांच अवधि के बाद उत्पाद का निर्यात किया है और उस कीमत पर विचार करते हुए जिस कीमत पर चीन के उत्पादकों ने भारत को निर्यात किया है, चीन के उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत को उत्पाद का निर्यात किए जाने की संभावना है।
- (ङ) याचिकाकर्ता ने अमरीकी पद्धतियों सहित अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की पद्धतियों का भी हवाला दिया है जिनमें अमरीकी प्राधिकारी कुछ स्थितियों में त्वरित समीक्षाएं करते हैं और खासकर तब जब विदेशी उत्पादकों से कोई उत्तर नहीं मिलता है या अपर्याप्त उत्तर मिलता है।
- (च) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन गण से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम हो जाने की संभावना है बशर्ते वर्तमान पाटनरोधी शुल्क पर विचार न किया जाए।
- (छ) चीन जन गण में निर्यातकों ने अपने घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं निर्मित की हैं। इसकी पुष्टि विभिन्न अन्य देशों को चीन जन गण से हुए पर्याप्त निर्यातों द्वारा होती है।
- (ज) चीन में अत्यधिक क्षमता उपलब्ध है। अपनी बेशी क्षमता के साथ चीन के उत्पादक पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में समूची मांग को पूरा कर

सकते हैं और इस प्रकार पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु को प्रस्तुत कर घरेलू उद्योग का समूचा बाजार हिस्सा हड़प सकते हैं ।

(vi) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन के उत्पादकों या निर्यातकों द्वारा पाटन की पुनरावृत्ति किए जाने की स्पष्ट संभावना है ।

(vii) याचिकाकर्ता ने उस कीमत का साक्ष्य उपलब्ध कराया है जिस कीमत पर चीन के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री की गई है और यह दावा किया है कि यद्यपि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए, तथापि इससे इस बात की स्पष्ट तौर पर पुष्टि होती है कि चीन में बिक्री कीमत (और इस प्रकार सामान्य मूल्य) काफी अधिक है और याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य इस बिक्री कीमत से काफी कम है ।

(viii) तीसरे देशों के जरिए उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विचाराधीन उत्पाद के आयात में भारी गिरावट आई है । याचिकाकर्ता ने इस संबंध में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई का हवाला दिया है । उल्लंघन की रोक थाम करने के लिए घरेलू उद्योग के प्रयासों के कारण आयातों में भारी कमी आई है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है ।

(ix) वर्तमान जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ था । तथापि आयातों में जनवरी (18 मी.टन) और फरवरी 2011 (120 मी.टन) के माह में काफी अधिक मात्रा में पुनः आयात होने की सूचना दी गई है । भारत में 7000 मी.टन की सकल मांग पर विचार करते हुए आयात की इस मात्रा को पर्याप्त माना जाना चाहिए । इसके अलावा ये आयात अत्यधिक कम कीमत पर सूचित किए गए हैं जिससे अत्यधिक पाटन का पता चलता है । याचिकाकर्ता ने इन आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया और यह दावा किया है कि पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन दोनों ही काफी अधिक हैं ।

(x) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का तीसरे देशों से हुए उत्पाद के निर्यातों से भारी अपवंचन किया गया है जो देश उत्पाद का विनिर्माण भी नहीं कर रहे हैं । आयात आंकड़ों से थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस आदि से विचाराधीन उत्पाद के आयात का पता चला है । इन देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के बारे में संगत सूचना मांगते हुए भारत में इन देशों के दूतावासों/मिशनो को पत्र भेजे गए थे । इनमें से किसी देश से कोई उत्तर नहीं मिला है । इसके अलावा मूल्यांकन निदेशालय, वित्त मंत्रालय तथा राजस्व आसूचना विभाग (डी आर आई) को पत्र भेजे गए थे । तत्पश्चात् उत्पाद के आयात में भारी गिरावट आई । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना का स्पष्ट पता चलता है ।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. वर्तमान जांच के संबंध में संबद्ध देश के किसी निर्यातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने पाटन और उसकी संभावना के निर्धारण की कार्यप्रणाली के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी के लिए शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित है।

छ. पाटन जारी रहना उसकी पुनरावृत्ति होना

25. धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समस्त ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। पाटन और पाटन मार्जिन के बारे में चीन जन गण के किसी उत्पादक/निर्यातक तथा भारत में आयातकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास असहयोगी निर्यातक हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अंतर्गत रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इस नियम में उपबंध है कि:-

“ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे ऐसी परिस्थितियों में उचित समझते हों।”

सामान्य मूल्य

26. धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत, जब वह उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की विशिष्ट बाजारी स्थिति अथवा घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना न हो सकता हो तो सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र या किसी उचित तीसरे देश से किया गया है; अथवा

- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत या लाभ के लिए उचित अभिवृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है ।

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में उपबंध है कि

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात होने की स्थिति में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकल्पित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे किसी तीसरे देश से कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहाँ ऐसा करना संभव न हो वहाँ आवश्यकतानुसार उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में संदेय या संदत्त कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और संदर्भाधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन उचित ढंग से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध किसी भरोसेमंद सूचना का पूरा ध्यान रखा जाएगा । किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संदर्भ में ऐसे किसी समान मामले में की गई जांच को जहाँ उचित समझा जाए, समय-सीमा के भीतर ध्यान में रखा जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के बारे में किसी अनावश्यक विलम्ब के बिना सूचित किया जाएगा और उसे टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी ।"

27. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उपर्युक्त उपबंधों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए । प्राधिकारी ने अनुबंध 1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार समस्त हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ मांगी थीं ।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उक्त अनुमान के खंडन के अधीन है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन तभी किया जा सकता है जब चीन जन गण के निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराएं और इसके विपरीत तथ्यों की पुष्टि करें । तथापि चीन में संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और न ही पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेखानुसार कोई सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है ताकि निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जा सके कि क्या:-

- (क) कीमत, लागत तथा कच्चे सामग्री सहित निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, उत्पादन, बिक्री तथा निवेश के बारे में चीन जन गण में संबंधित फर्मों के निर्णय

इस संबंध में राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप के बिना मांग और आपूर्ति को प्रदर्शित करने वाले बाजारी संकेतकों की प्रतिक्रिया स्वरूप लिए जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है:

- (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति, खासकर परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋण प्रतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से ली गई पर्याप्त विकृतियों के अधीन है।
- (ग) ऐसी फर्मों द्वारा दिवालियापन तथा संपत्ति कानूनों के अधीन है जो फर्मों के प्रचालन हेतु विधिक निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान के खंडन की मांग नहीं की है इसलिए प्राधिकारी इस बात पर विचार करने के लिए असमर्थ हैं कि क्या वर्तमान मामले में चीन के एक या अधिक उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी चीन के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुए हैं।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता जिसका कारण यह है कि उक्त देश के किसी उत्पादक की ओर से संगत सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है।

31. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और चीन के उत्पादकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने "किसी अन्य आधार" पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित समझा है और उन्होंने उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

ज. चीन के मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली

32. प्राधिकारी ने निम्नलिखित आधार पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है:-

- (क) प्रमुख निविष्टियों की लागत पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर विचार किया गया है।

- (ख) उत्पादन की प्रति इकाई कच्ची सामग्री की खपत पर घरेलू उद्योग के सत्यापित खपत मानकों के आधार पर विचार किया गया है ।
- (ग) परिवर्तन लागत पर घरेलू उद्योग के कुशल उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है ।
- (घ) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत (ब्याज लागत सहित) को घरेलू उद्योग के कुशल उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर लिया गया है ।
- (ङ) ब्याज को छोड़कर कारखाना लागत के 5 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़ा गया है ।

झ. निर्यात कीमत

33. धारा 9 क (1) (ख) के अंतर्गत निर्यात कीमत का तात्पर्य है:

किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात कीमत" का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत से है अथवा जहाँ निर्यात कीमत नहीं है अथवा जहाँ उक्त निर्यात कीमत निर्यातक और आयातक अथवा किसी तीसरे पक्षकार के बीच एसोसिएशन अथवा किसी क्षतिपूर्तिकारी व्यवस्था के कारण विश्वसनीय नहीं है वहाँ निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिस कीमत पर आयातित वस्तुओं की सर्वप्रथम पुनः बिक्री किसी स्वतंत्र विक्रेता को की जाती है अथवा यदि उक्त वस्तु की पुनः बिक्री किसी स्वतंत्र विक्रेता को नहीं की जाती है अथवा आयातित वस्तु की स्थिति में पुनः बिक्री नहीं की जाती है वहाँ परिकलन ऐसे उचित आधार पर किया जा सकता है जिसे उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाए ।

34. निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्राधिकारी ने समस्त ज्ञात निर्यातक/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी । संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने कोई सूचना दायर नहीं की है ।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान चीन जन गण से संबद्ध उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है । अतः जांच अवधि के दौरान बाद में हुए वास्तविक आयातों को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि में हुए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

ञ. पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

पाटन जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण

36. यह नोट किया जाता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन

एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार 22 जून, 2010 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई है। इस प्रकार किसी निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

37. पूर्ववर्ती पैराग्राफ से यह नोट किया जाता है कि समीक्षा जांच अवधि के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई आयात न होने के मद्देनजर जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का पाटन जारी नहीं रहा है।

पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण

38. पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी का प्रस्ताव उस कीमत के बारे में रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य पर भरोसा करने का है जिस कीमत पर चीन जन गण से वस्तु का निर्यात कई अन्य देशों को किया गया है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन गण से अन्य देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया गया है और वर्ल्ड ट्रेड एटलस से लिए गए निर्यात के विवरण से यह पता चलता है कि उसने 1.37 अम.डा./किग्रा. की औसत कीमत पर 10.07 मिलि.अम.डा. के कुल मूल्य की संबद्ध वस्तु के 7378 मी.टन का निर्यात किया है। जांच अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात न होने के कारण प्रस्ताव है कि चीन जन गण से अन्य देशों को हुए संबद्ध वस्तु के निर्यात को लिया जाए क्योंकि संभावना के आधार पर संभावित निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया गया है :

	सामान्य मूल्य (अम.डा./किग्रा.)	निर्यात मूल्य (अम.डा./किग्रा.)	पाटन मार्जिन (अम.डा./किग्रा.)	पाटन मार्जिन%
(I) तीसरे देशों को हुए निर्यातों पर विचार करते हुए				
सभी उत्पादक एवं निर्यातक	1.50	1.37	0.14	10.08

39. जांच अवधि के बाद की आवधि के लिए जनवरी-दिसम्बर, 2010 के दौरान अन्य देशों को निर्यात पर आधारित संभावित पाटन मार्जिन लगभग 17% है।

40. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शुल्क को निरंतर लगाए जाना पाटन को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है:-

- (क) प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार करते हुए पाटन की संभावना का निर्धारण किया है जिस कीमत पर वस्तु का निर्यात अन्य देशों को किया गया है ।
- (ख) मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान तथा संभावित क्षमता, भारत में प्रचलित कीमत, निर्यातों की वास्तविक और संभावित मात्रा, अन्य देशों को चीन जन गण से हुए निर्यात की कीमत ।
- (ग) मात्रा और वह दर जिस पर चीन जन गण से संबद्ध वस्तु जांच के तुरंत बाद की अवधि में आयी है ।

41. इन कारकों की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि

- (क) वर्तमान जांच में किसी भी उत्पादकों के निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है । यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है और पाटन समाप्त करने के लिए शुल्क को निरंतर लगाना अनावश्यक है । प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है ।
- (ख) यह नोट किया जाता है कि चीन जन गण के उत्पादकों ने जांच अवधि के लिए निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य से अत्यधिक कम कीमत पर अन्य देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है । जांच अवधि और जांच अवधि के बाद दकी अवधि के दौरान भी अन्य देशों को एसएफएस की निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन की संभावना काफी अधिक है । रिकॉर्ड से यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन गण के विरुद्ध चीनी ताइपेई द्वारा संबद्ध वस्तु के बारे में सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और चीन जन गण पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन गण में एस एफ एस की बिक्री 1.6 अम.डा./किग्रा. की कीमत पर की गई है । इसके अलावा, प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के बाद भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात 1.13 अम. डॉ./कि.ग्रा. की दर से किया गया है जिससे अत्यधिक पाटन का पता चलता है ।
- (ग) रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएँ हैं । उत्पादक के पास न केवल पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं अपितु ये उत्पादक विभिन्न देशों को अत्यधिक निर्यात भी कर रहे हैं । घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार चीन जन गण संबद्ध वस्तु की क्षमता, उत्पादन और मांग निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2006	2011
1	चीन की क्षमता	मी.टन	19600	24600
2	उत्पादन	मी.टन	14700	21000
3	अप्रयुक्त क्षमता (आंकड़े का अंतर)	मी.टन	4900	3600
4	चीन की क्षमता	मी.टन	19600	24000
5	चीन की मांग	मी.टन	9100	13000
6	चीन जन गण में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता	मी.टन	10500	11000
7	भारतीय मांग	मी.टन	7004	7004
8	भारतीय मांग की अधिशेष क्षमता का %	%	150	166
9	अप्रयुक्त क्षमता	मी.टन	4900	3600
10	भारतीय मांग के अप्रयुक्त क्षमता का %	मी.टन	69.96	51.4

(घ) प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से यह नोट किया जाता है कि चीन जन गण में पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। इसके अलावा चीन के उत्पादक कई देशों को निर्यात कर रहे हैं और इसलिए तीसरे देश को होने वाले निर्यात भारत में भेजे जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जाता है।

पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में निष्कर्ष

42. उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटन की पुनरावृत्ति होने की अत्यधिक संभावना है।

क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा कारणात्मक संबंध का निर्धारण

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा होने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहने और वास्तविक क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के वास्तविक या संभावित आयातों के संदर्भ में करना जरूरी है।

घरेलू उद्योग के विचार

44. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:-

(i) प्राधिकारी के लिए किसी निर्णायक समीक्षा मामले में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध-11 की अपेक्षाओं तक सीमित रहना अपेक्षित नहीं है और समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध की जांच करना अपेक्षित नहीं है। ओ टी सी जी के मामले में डब्ल्यू टी ओ निर्णय का हवाला दिया गया है और भरोसा किया गया है।

(ii) ऐसी स्थिति में जहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई सतत क्षति नहीं हुई है वहाँ याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करे। यद्यपि घरेलू उद्योग लागू शुल्क के कारण सकारात्मक निष्पादन प्रदर्शित कर रहा है तथापि घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है।

(iii) घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है जिसकी पुष्टि अत्यधिक सकारात्मक कीमत कटौती, संबद्ध देश में विदेशी उत्पादकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता (अन्य तीसरे देश के बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में उच्च कीमतें), संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा तीसरे देश के बाजारों में पाटन द्वारा की गई है। वर्तमान मामले में आंकड़ों/सूचना के विश्लेषण से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को प्रतिकूल मात्रात्मक क्षति और कीमत क्षति दोनों होने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने लागू शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संभावित मात्रात्मक क्षति और संभावित कीमत क्षति की मात्रा ज्ञात की है।

(iv) वर्तमान मामले में शुल्क लागू होने के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि होने की संभावना है जिसका कारण है (1) संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमता, (2) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, (3) तीसरे देश में पाटन।

(v) विदेशी उत्पादकों के पास वर्तमान क्षमता पहले से ही निर्यातक देश में मांग से अधिक है। क्षमताएं उपयोग में लाई जा चुकी हैं। इसके अलावा, नई क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं।

(vi) संबद्ध वस्तु के बारे में संबद्ध देश के निर्यातकों और वह भी पाटित कीमतों पर होने के दुष्प्रभाव से घरेलू उद्योग बिक्री घाटे के विकल्प के रूप में भारतीय घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत को घटाने के लिए बाध्य या विवश होगा।

(vii) अतः यह अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को घटती हुई बिक्री मात्रा और कीमत कटौती के बीच का रास्ता चुनना होगा। यदि घरेलू उद्योग कीमत को बराबर करता है तो कीमत में गिरावट काफी अधिक होगी।

(viii) प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान एसएफएस का उत्पादन न करने वाले देशों और इसका उत्पादन करने वाले देशों के जरिए पाटनरोधी शुल्क के अपवंचन के अपने आक्षेप की ओर आकर्षित किया है। उसने प्राधिकारी का ध्यान चीन जन. गण. से एसएफएस के आयातों पर चीनी ताइपेई द्वारा पर्याप्त पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की ओर पुनः आकर्षित किया है। उसने यह भी उल्लेख किया है कि अत्यधिक पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए चीन क उत्पादक वैकल्पिक बागाजारों की तलाश करेंगे। उसने आगे उल्लेख किया कि

जांच अवधि से पूर्व और जांच अवधि के बाद चीन जन. गण. से अत्यधिक पाटित कीमत पर भारी मात्रा में हुए आयात से पाटन एवं क्षति की संभावना की पुष्टि होती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि आयातों की संभावित पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू बाजार में अत्यधिक कीमत कटौती होने की संभावना है। इसके अलावा, चीन से तीसरे देशों को आयात की संभावित पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है जिससे अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हो रही है। उसने उल्लेख किया कि बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण क्षति अवधि की शुरुआत में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और पाटित आयातों में कमी के साथ ही घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। पाटन होने पर क्षति की मौजूदगी और पाटन न होने पर कोई क्षति न होने से पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना की पुष्टि होती है। शुल्क की राशि और स्वरूप के बारे में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामला निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण शुल्क की राशि वही रहनी चाहिए जैसी कि मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सिफारिश की है। शुल्क की राशि और स्वरूप के बारे में उसने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :

क) पाटनरोधी शुल्क की राशि लागू रखने हेतु घरेलू उद्योग का मामला पाटन एवं क्षति की संभावना पर आधारित है और इसलिए पाटनरोधी शुल्क की वही राशि लागू रखी जानी चाहिए।

ख) चूंकि वर्तमान पाटन जांच अवधि में भारत को कोई निर्यात नहीं हुआ है इसलिए पाटनरोधी शुल्क की राशि को या तो पाटन जांच अवधि से पूर्व या उसके बाद हुए आयातों पर आधारित किया जाना चाहिए या फिर प्राधिकारी को मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की राशि को बढ़ाना चाहिए।

ग) यद्यपि तीसरी देशों को कोई निर्यात नहीं हुआ है तथापि इसका उपयोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा पाटन एवं परिणामी क्षति का सामना किए जाने की संभावना है, इनका उपयोग पाटनरोधी शुल्क की राशि निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अन्य कारणों में वे देश आते हैं जहां कोई घरेलू उत्पादन नहीं होता है और भारत तथा तीसरे देशों को हुए निर्यातों के बीच कीमत अंतर से स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि तीसरे देशों के लिए निर्यात कीमत से पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संभावित पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की पुष्टि नहीं होती है।

घ) नियमों में यह निर्धारण करने का प्रावधान है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की राशि में आगे और वृद्धि की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य शुल्क में वृद्धि करने या न करने के बारे में किसी निर्णय से है। यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने व्यावहारिक तोर पर पाटनरोधी शुल्क की राशि में संशोधन करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग किया है तथापि ऐसा अवसर तब उपलब्ध नहीं होता है जब मामला पाटन एवं क्षति की संभावना पर आधारित हो।

(ङ.) कनाडा, अमरीका तथा यूरोप जैसे तीसरे देशों द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अंतर्गत यह निर्णय लेना होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की राशि बढ़ाई गई अथवा नहीं। ये देश पाटनरोधी

शुल्क की राशि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं भले ही जांच अवधि में अत्यधिक आयात हुए हों और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन (ईसी) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से काफी कम हो ।

(च) ऐसे पूर्ववर्ती उदाहरण उपलब्ध हैं जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समीक्षा मामले में पाटन मार्जिन मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन से कम होने के बावजूद भी अपनी मूल जांच में की गई संस्तुति के अनुसार शुल्क की वही राशि लागू की है । ईयू के एक मामले सहित ऐसे कुछेक ज्ञात मामले निम्नानुसार हैं :-

- (i) ईरान इस्लामिक गणराज्य के मूल के या वहाँ से निर्यातित हेक्सा मिथाइलीन टेट्रामाइन (अक्सामिन) के आयातों से संबंधित मामले में निर्णायक समीक्षा जांच ।
- (ii) सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका तथा यूरोपीय संघ के मूल के या वहाँ से निर्यातित फेनॉल के आरोपित पाटन के बारे में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच ।
- (iii) यूएई तथा ईरान के मूल के या वहाँ से निर्यातित व्हाइट सीमेंट के आयातों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच ।
- (iv) 20 दिसम्बर, 2010 का परिषद कार्यान्वयन विनियम (ईयू) सं. 1242/2020 जिसके तहत विनियम (ईसी) सं. 1225/2009 के अनुच्छेद 11(2) के अनुसरण में कालातीत समीक्षा के बाद भारत के मूल के सिंथेटिक फाइबर के रस्सों के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

(छ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क की राशि वही रखने का अनुरोध किया है जैसी कि मूल जांचों के दौरान निर्धारित किया गया है ।

निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

45. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

46. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है ।

47. प्राधिकारी ने शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है । यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 9 (5) के अनुसार शुरू की गई है जिसमें प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क को आगे और 5 वर्ष की अवधि तक जारी रखना जरूरी है और संभावित पाटन एवं क्षति की मात्रा और सीमा तथा प्रदत्त सूचना के आधार पर शुल्क जारी रहने या समाप्त करने की जरूरत तथा जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच करना अपेक्षित है । क्षति अवधि के दौरान वर्तमान क्षति का निर्धारण करना

अथवा क्षति जारी रहने का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव की जांच की है।

ट. मांग और बाजार हिस्से का निर्धारण

48. मांग और बाजार हिस्से के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री और विभिन्न स्रोतों से हुए आयातों पर विचार किया है। भारत में उत्पाद की मांग की गणना भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और विभिन्न देशों से हुए ज्ञात आयातों की मात्रा के रूप में की गई है। इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:-

		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
संबद्ध देश - चीन जन गण	मी.टन	20	200	20	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1000	100	0
अन्य देश	मी.टन	560	198	80	2
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	3507	3390	3422	4597
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98	131
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	1690	1520	1835	2405
कुल मांग - आबद्ध खपत को छोड़कर	मी.टन	5777	5308	5357	7004
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	93	121
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश - चीन जन गण	%	0%	4%	0%	0%
अन्य देश	%	10%	4%	1%	0%
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	61%	64%	64%	66%
अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	29%	29%	34%	34%
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

49. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में सुधार हुआ है।

मात्रात्मक प्रभाव

50. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वास्तविक या संभावित वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपबंध है:

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

51. इस अवधि के दौरान आयातों की वास्तविक मात्रा निम्नानुसार रही है:-

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आयात मात्रा					
चीन जन गण	मी.टन	20	200	20	-
अन्य देश	मी.टन	560	198	80	2
कुल आयात	मी.टन				
आयातों में बाजार हिस्सा					
चीन जन गण	%	3.45	50.25	20.00	-
अन्य देश	%	96.55	49.75	80.00	100.00
मांग में बाजार हिस्सा					
चीन जन गण	%	0.35	3.77	0.37	0.00
अन्य देश	%	9.69	3.73	1.49	0.02

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसमें भारी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष जब मांग में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से कोई आयात दर्ज नहीं किया गया है।

कीमत प्रभाव

53. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"नियम 18 के उप-नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

क्षति अवधि के दौरान कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बिक्री मूल्य	रूपये/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	86	86
निवल बिक्री प्राप्ति	रूपये/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	116	118

54. कीमत ह्रास तब होता है जब उद्योग की कीमतें पूर्ववर्ती अवधि के स्तर से कम होती है। कीमत न्यूनीकरण तब होता है जब पाटन के कारण कीमत वृद्धि में रूकावट आती है जो अन्यथा लागत में वृद्धि के कारण बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की लागत और कीमत संरचना से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में लागत में लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की कीमत में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि बिक्री लागत में गिरावट आई है जबकि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है।

55. किसी निर्णायक समीक्षा जांच में इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों का अत्यधिक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है अथवा क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पर्याप्त प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

56. प्राधिकारी ने आगे यह निर्धारित किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री का सामना करने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन जन गण से अन्य देशों को संबद्ध वस्तु की कीमत के रूप में चीन जन गण से संभावित निर्यात कीमत तथा उस कीमत पर विचार किया है जिस कीमत पर समीक्षा जांच अवधि के तुरंत बाद चीन जन गण से भारत में संबद्ध वस्तु का आयात हुआ है और उसकी तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण से संभावित कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है।

घरेलू उद्योग से संबंधित अन्य आर्थिक मापदंड

57. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इसके अलावा, नियमावली के अनुबंध-II (iv) में निम्नानुसार निर्धारित है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त आर्थिक कारकों और

संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

उत्पादकता, क्षमता तथा क्षमता उपयोग, बिक्री

58. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
स्थापित क्षमता	मी. टन	8,000	8,000	10,500	10,500
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	131	131
उत्पादन	मी. टन	6,273	8,020	7,876	9,518
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	126	152
क्षमता उपयोग	%	78%	100%	75%	91%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	96	116
आबद्ध अंतरण	मी. टन	149	187	226	319
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	152	215
घरेलू बिक्री	मी. टन	3,507	3,390	3,422	4,597
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98	131
आबद्ध खपत को छोड़कर मांग	मी. टन	5776	5308	5357	7004
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	93	121
मांग में बिक्री का %	मी. टन	61%	64%	64%	66%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	105	108

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

60. घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री में समग्र रूप में और भारत में उत्पाद की मांग/खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

61. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह की जांच निम्नानुसार की गई है:-

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
कर पूर्व लाभ	रुपए/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(66)	21	33
कर पूर्व लाभ एवं कर	रुपया/लाख	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(64)	27	39
लगाई गई पूंजी पर आय (एन एफ ए आधार)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(70)	23	24
नकद लाभ	रूपया/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(66)	27	42

62. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लाभ प्रदत्ता में भारी सुधार हुआ है।

रोजगार एवं मजदूरी

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का संघटक एक बहु-उत्पाद कंपनी है; अतः पाटन का घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ सकता है। घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और मजदूरी की स्थिति निम्नानुसार रही है:-

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	116	123
मजदूरी	रूपया/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	111	167

64. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में सुधार प्रदर्शित हुआ है। इसके अलावा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मजदूरी के स्तर में भी वृद्धि हुई है।

उत्पादकता

65. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन	47	57	51	58
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	108	124
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन	18	23	23	27
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	126	152

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में उत्पादन के अनुसार सुधार हुआ है ।

मालसूची

66. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर की जांच की है जिसे निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
औसत स्टॉक	मी. टन	247	179	88	32
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	36	13
बिक्री दिनों की संख्या के संदर्भ में औसत स्टॉक	दिनों की संख्या	26	19	9	3
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	37	10

उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर में गिरावट आई ।

पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

67. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण घरेलू उद्योग की पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने और परिणामतः पाटन पर अंकुश लगने के कारण विचाराधीन उत्पाद में नया निवेश किया है ।

वृद्धि

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग ने उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूँजी पर आय जैसे समस्त आर्थिक मापदण्डों के संबंध में सकारात्मक वृद्धि की है ।

पाटन की मात्रा

69. यह नोट किया जाता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई पाटन नहीं हुआ है क्योंकि संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ है ।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

70. पाटित आयातों से इतर जिन अन्य कारकों से घरेलू बाजार में कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, उन कारकों का विश्लेषण करने के लिए लागत संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग में

प्रतिस्पर्धा की जाँच की गई है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण इस समीक्षा जाँच की क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों पर किसी बाह्य कारक का प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्षति की मात्रा और क्षति निर्धारण

71. चूँकि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की कोई निर्यात कीमत नहीं है इसलिए जाँच अवधि के दौरान कोई क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा वर्तमान क्षति के बारे में निष्कर्ष

72. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग ने उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय जैसे समस्त आर्थिक मापदण्डों के संबंध में सकारात्मक वृद्धि की है। इस प्रकार जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत संबंधी मापदण्डों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षति अवधि के दौरान विभिन्न क्षति मापदण्डों के उपर्युक्त विश्लेषण से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

73. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है।

अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमत

74. यह नोट किया जाता है कि जाँच अवधि के दौरान अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात लगभग नगण्य या शून्य रहा है।

माँग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

75. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की माँग में नकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। इस प्रकार, माँग में कमी ऐसा संभावित कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जाँच अवधि
माँग	मी. टन	5777	5308	5357	7004

76. खपत की पद्धति में परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्राधिकारी की जानकारी में नहीं आया है।

विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

77. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात होती है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है। घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है और साथ-ही-साथ संबद्ध वस्तु की पहुँच कीमत से प्रतिस्पर्धा करती है।

प्रौद्योगिकी विकास

78. यह नोट किया जाता है कि उत्पाद के उत्पादन के प्रौद्योगिकी में न तो कोई खास परिवर्तन हुआ है और न ही भविष्य में परिवर्तन होने की संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी विकास क्षति का संभावित कारक प्रतीत नहीं होता है। याचिकाकर्ता द्वारा पिछले कई वर्षों से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी विश्व के अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय है। वस्तुतः यह अनुरोध किया गया है कि उत्पाद की प्रौद्योगिकी बहुत कम प्रौद्योगिकीय नवीकरणों और विकास के साथ पूर्णतः परिपक्व, सुस्थापित और मानकीकृत है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। उत्पादकता में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता नहीं चलता है।

क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना

प्राधिकारी द्वारा जाँच

80. प्राधिकारी द्वारा जाँच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना और साक्ष्य के आधार पर सतत क्षति की जाँच के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की भी जाँच की गयी है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदण्डों पर विचार करते हुए क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की भी जाँच की है। इस नियम में निम्नानुसार उल्लेख है :

“ वास्तविक क्षति के किसी खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरवर्ती संभावना पर उन परिस्थितियों में परिवर्तन, जिनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट तौर पर पूर्वानुमानित और आसन्नवर्ती होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के बारे में कोई निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे; और

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की पर्याप्त दर जिससे अत्यधिक संवर्धित आयात की संभावना का पता चलता हो

(ख) निर्यातक की पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य अथवा आसन्नवर्ती, क्षमता में अत्यधिक वृद्धि जिससे अतिरिक्त निर्यातों को खपत करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त संवर्धित पाटित निर्यातों की संभावना का पता चलता हो

(ग) क्या आयात ऐसी कीमत पर हो रहे हैं जिसका घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा जिससे आगे और आयात करने की माँग में वृद्धि होगी, और

(घ) वस्तु की मालसूचियों की जाँच की जा रही है । ”

81. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि निर्णायक समीक्षा में इस बात की जाँच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक तथा किसी भी भारतीय आयतक/उपभोक्ता ने इस समीक्षा जाँच में उत्तर नहीं दिया है । घरेलू उद्योग ने उसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचनाओं के आधार पर निर्यातक देश में संबद्ध वस्तु की क्षमता, उत्पादन और माँग के बारे में सूचना प्रदान की है । अतः प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए ऐसे सभी कारकों की जाँच की गई है ताकि यह पता लगाना जा सके कि क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

82. जाँच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का कोई आयात न होने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जाँच करने के लिए प्राधिकारी ने उसी अवधि के दौरान चीन जन. गण. से अन्य देशों को हुए संबद्ध वस्तु के निर्यातों को ध्यान में रखा है । इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पहुँच कीमत (अन्य सभी देशों के लिए सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए) तथा क्षति रहित कीमत की जाँच के आधार पर यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देश से आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम रहा है । प्राधिकारी ने उस कीमत की भी जाँच की है जिस कीमत पर जाँच अवधि के तुरंत बाद भारत में संबद्ध वस्तु का आयात किया गया है और यह नोट करते हैं कि जाँच अवधि के तुरंत बाद चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है ।

83. लागू उपाय समाप्त होने के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देश में अपना उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने की संभावना है । इसके अलावा, इस बात की संभावना है कि इस उपाय के अभाव में संबद्ध देश का उत्पादक पाटित कीमतों की नीति अपनाएगा जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है जिसमें संबद्ध देश से पाटित आयातों के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण सुधार और भरपाई प्रदर्शित होती है । घरेलू उद्योग ने शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध देश से आयातों की संभावित मात्रा और किए जाने वाले ऐसे

आयातों की संभावित कीमत तथा ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव के बारे में विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किए ।

84. प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. की संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात किए जाने की संभावना है और संबद्ध देश के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं तथा बेशी स्टॉक उपलब्ध होने के कारण उनके द्वारा भारतीय बाजार में और अधिक मात्रा में पाटित निर्यात किए जाने की संभावना है ।

85. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन. गण. से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के संभावित प्रभाव की जांच की है और यह नोट किया है कि संबद्ध देश से तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के स्तर, निर्यातक देशों के पास उपलब्ध बेशी/मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता जैसे कारकों से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है । वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयातों में आगे और वृद्धि होने की संभावना है । अतः यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर आयात किए जाने और घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है ।

86. यह भी नोट किया जाता है कि चीनी ताइपेई ने चीन जन. गण. से एसएफएस पर पाटनरोधी शुल्क वर्ष 2010 के दौरान लगाया था और इसकी प्रति सार्वजनिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत की है । शुल्क 14% से 28% के बीच है । यह नोट किया जाता है कि चीनी ताइपेई द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से चीन जन. गण. के संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के लिए बाजार का नुकसान हो सकता है और जांच अवधि के बाद पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा अधिक हो सकती है ।

पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में निष्कर्ष

87. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किए गए उपर्युक्त विश्लेषण से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात की पुनरावृत्ति होने और प्रतिकूल मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है और इस बात की भी भारी संभावना है कि अत्यधिक मात्रा में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

88. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है । तथापि पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं

होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेंगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

निष्कर्ष

90. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना तथा किए गए अनुरोधों और उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों एवं पाटन तथा परिणामी क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (i) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु के पाटित कीमतों पर प्रवेश किए जाने की संभावना है।
- (ii) पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की अनुमति दिए जाने से घरेलू उद्योग की स्थिति खराब होने की संभावना है।
- (iii) घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आने की संभावना है।
- (iv) अतः पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना अपेक्षित है।

ठ. सिफारिशें

91. इस आशय का निष्कर्ष निकालने के बाद कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि चीन जन. गण. से आयातों के संबंध में इस उपाय को लागू रखना अपेक्षित है।

92. लागू वर्तमान उपाय को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की आसन्नवर्ती संभावना की जांच करने के बाद प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित दिनांक 25.1.2006 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं. 14/25/2004-डीजीएडी के तहत संस्तुत और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 6.3.2006 की अधिसूचना सं. 23/2006-सी.शु. के तहत अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

93. इस सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ उत्पन्न होने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****(Sunset Review)**

New Delhi, the 17th June, 2011

Sub. : Sunset Review Investigation of anti-dumping duty imposed against imports of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) originating in or exported from China PR.

No. 15/16/2009-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A. BACKGROUND

2 WHEREAS, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation on 28th Jan, 2005 into alleged dumping of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) originating in or exported from China PR and provisional antidumping duty was imposed on imports of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate from China PR vide customs notification no. 95/2005-CUS dated 11th Nov 2005 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 26th Aug 2005. The final findings were notified vide notification dated 25th Jan 2006 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from subject country vide notification no. 23/2006 -CUS dated 6th Mar 2006.

3 And whereas, the Act and the Rules require the Authority to conduct review of anti dumping duty earlier imposed. Hon'ble Delhi High Court has also held in WP No. 16893 of 2006 that sunset review is mandatory in order to determine whether cessation of the existing duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury. Therefore the Authority initiated a sunset review investigation vide notification dated 22nd June 2010 in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And whereas antidumping duty as notified vide Notification No. 23/2006 Customs dated 6th Mar 2006 was extended up to 21st June, 2011 vide notification

No. 114 /2010-Customs dated 1st November, 2010 in terms of Section 9(A)(5) of the Act.

B. GENERAL PROCEDURE

5 The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i) In pursuance to the notification issued by the Designated Authority dated 22nd June 2010, the Designated Authority under the above Rules, received an application filed by Transpek-Silox Industry Limited, supported by Demosha Chemicals Pvt. Limited for the review, continuance and enhancement of anti dumping duty in force against dumping of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) in the Indian market by the producers and/or exporters from China PR.
- ii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject country and provided them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2)
- iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).
- iv) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, on request.
- v) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject country, including known exporters/producers in accordance with the Rule 6(4). However none of the exporters/producers from the subject country filed response to the questionnaire.
- vi) Questionnaire was sent to known importers or user for providing necessary information in accordance with Rule 6(4). The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. However none of the importers filed response to the questionnaire
- vii) The Authority held a public hearing on 18th Jan 2011 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally, which was attended by Transpek-Silox Industry Limited, Demosha Chemicals Pvt. Limited and TPM Consultants (consultants for Transpek-Silox Industry Limited). The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. Designated Authority has considered these written submissions received from interested parties. However none of the producers/exporters or importers attended the public hearing and therefore has not

submitted the written submissions. The Authority held another public hearing on 30th March 2011 to provide another opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6(6). It is noted that in this second hearing also, none of the interested parties except the domestic industry participated in the public hearing. Arguments raised and information/evidence provided by the interested parties during the course of the investigation, to that extent the same are considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

- viii) Arguments raised and information/evidence provided by domestic industry during the course of the investigation, to that extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, shall be appropriately considered by the Authority in the findings.
- ix) The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. For that purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary. Additional/ supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.
- x) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have been considered in Final Findings.
- xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by domestic industry through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xii) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiii) **** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.
- xiv) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2009 to 31st March 2010 (12 months and has been referred to as the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2006-07, 2007-08, 2008-09 and POI.
- xv) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority shall record findings on the basis of the facts available.

- xvi) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

6. The product under consideration in the present investigation is Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (referred to as SFS or subject goods in the present investigation) originating in or exported from China PR (referred to as subject country in the present investigation).

VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

7. Domestic industry has made following submissions:-

- (i) The present investigation is for the review, enhancement and continuance of anti dumping duty in force against dumping of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate in the Indian market by the producers and/or exporters of China PR.
- (ii) Being a review investigation, product under consideration should be considered the same as has been in the original investigation.
- (iii) The product under consideration in the present investigation is Sodium Formaldehyde Sulfoxylate. The complete description of the product including nomenclature, formula, description, grades, uses, packing, transport, classification, handling etc. in respect of the product under consideration being imported from the subject country is already examined by the Designated Authority in the original investigations and the relevant information is on record of the Designated Authority.
- (iv) Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) is mainly used as powerful discharging agent in textile printing. It can also be used as white discharging agent or colour discharging agent. In the rubber industry it is used as an activating agent in the production of styrene-butadiene rubber. It also finds uses in Food, Polymers, Pharmaceuticals and Miscellaneous industries.
- (v) There is no known difference in Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) exported from China PR and Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) produced by the petitioner company. The goods produced by the domestic industry are like article to the goods imported from China PR. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.
- (vi) The goods produced by the domestic industry are like article within the meaning of anti dumping Rules.

VIEWS OF THE IMPORTERS, CONSUMERS, EXPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

8. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, like articles and scope of the present investigations

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

9 The product under consideration in the present investigation is Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (referred to as SFS or subject goods in the present investigation) originating in or exported from China PR (referred to as subject country in the present investigation). The product under consideration is the same as considered in the original investigation.

10. Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No 28311020. The Custom classification is, however, indicative only and not binding on the scope of investigations.

11 In the initiation notification, the scope of the product under consideration was specified as follows –

The product under consideration in the previous investigations and the present sunset review is Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS). It is an inorganic chemical, in the form of white chips, powder, rice- pea sized granules with slight characteristic odour. SFS is produced by chemical reaction of zinc dust, water and sulphur dioxide. There is no material difference in the different forms of the product. Production of different forms depends on the requirement of end application of the customer and different forms serve the same general purpose. Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) is mainly used as powerful discharging agent in textile printing. It can also be used as white discharging agent or colour discharging agent. In the rubber industry it is used as an activating agent in the production of styrene-butadiene rubber. It also finds uses in food, polymers, pharmaceuticals and miscellaneous industries.

12 Having regard to the evidence of record and initiation notification, the Authority considers it appropriate to keep the scope of the product under consideration to the same as was kept before. The Authority therefore has defined the product under consideration as Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS).

13 In order to determine whether goods produced by the domestic industry can be considered like article to the goods produced and/or exported from the subject country, Designated Authority notes that the issue has been examined by the Designated Authority and no submissions has been received by the Designated Authority, opposing previous determination of the Authority. The Authority, on the basis of the examination, holds that the material produced by the domestic

industry is like article to the goods imported or produced in subject country within the meaning of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY

VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

14. The Domestic industry made following submissions regarding domestic industry.

(i) The present petition was filed by M/s Transpek-Silox Industry Limited and supported by M/s. Demosha Chemicals Pvt. Limited. As regards the production of subject goods by TCP Limited, the petitioner submits that there has been insignificant production by the said company during the injury period.

(ii) The production of petitioner accounts for more than 50 per cent of the total Indian production (it was in fact about 65.6% of Indian production). Thus, petitioner accounts for "a major proportion in total Indian production".

VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

15. None of the other interested parties filed any submissions in this regard.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

16. According to the Rule 2 (b), "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

17. The production of the petitioner company constitutes a major proportion in the Indian production. Further, the petition was supported by M/s. Demosha Chemicals Pvt. Limited. Therefore, the petition is considered to have been made by the domestic industry within the meaning of Anti Dumping Rules.

18. Based on the Information available on records of the Designated Authority, petitioner and supporters account for major proportion of Indian production and constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

E. OTHER ISSUES

VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

19. The Domestic industry has submitted as under:-

(i) The petition was complete in all respect and adequate and accurate evidence was provided to the Authority post initiation.

(ii) None of the exporters have responded to the questionnaire issued by the Authority. Exporters should therefore be considered non-cooperative as per Rule 6(8) and the Authority should proceed according to the best information available.

(iii) Sodium Formaldehyde Sulphoxylate are reported to have been exported to India from China, Taiwan, Thailand, Indonesia, Germany and Russia in the year 2006-07 & 2007-08 and from Iran in the year 2008-09. The petitioner submits that the apart from India and China, there are only two countries who have manufacturing set up of the product under consideration, namely Europe and Taiwan. Therefore the imports to India from Thailand, Indonesia and Russia are mere case of transshipment because of the absence of manufacturing set up in these countries.

VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

20. None of exporter from subject country filed any response with regard to the present investigation.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

21. The Designated Authority has noted the submissions made by interested party and issues have been examined under appropriate headings in this final finding in accordance with the Rules.

CALCULATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

A.

B.

C.

F. DUMPING MARGIN

VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

22. The domestic industry has submitted as under:

(i) Petitioner claims that China should be treated as non market economy for the purpose of determination of normal value. Further, there is no claim from a Chinese producer or exporter for market economy treatment. None of the Chinese exporters have filed questionnaire response, nor claimed market economy treatment. Such being the case, question of applying para-8 of Annexure-I and considering whether the Chinese companies are entitled for market economy treatment does not arise.

- (ii) In the original investigations, the Authority has not granted market economy treatment to any of the responding exporter from China PR.
- (iii) The petitioner has treated Europe as an appropriate surrogate country in its petition. The Authority may consider treating Europe as an appropriate surrogate country. In the alternative, the Authority may consider India as an appropriate country for the purpose of determination of normal value .
- (iv) There are no imports of the product under consideration in the current POI. In a situation where there are no continued imports, the Designated Authority shall come to a conclusion that there is no continued dumping. However, non existence of continued imports in POI does not imply a need for revocation of anti dumping duties. The same merely implies that the Designated Authority shall determine whether there is likelihood of recurrence of dumping. Petitioner has referred to the practices of other countries as well where anti dumping duties have been extended despite no exports in POI.
- (v) Likelihood of recurrence of dumping is established from the following :
- a) Even though there were no exports during the POI, there are exports during the injury period. Petitioner has determined dumping margin in respect of these exports and has claimed that these exports were at significant dumping prices.
 - b) There were exports of the product after the POI. These exports were also at significant dumping prices.
 - c) Exports of product under consideration from China to third country are at significantly dumping prices.
 - d) Considering the prices at which the Chinese producers have exported the product to India during the injury period and after the POI and considering the prices at which the Chinese producers have exported to India, the Chinese producers are likely to export the product to India at dumping prices.
 - e) Petitioner also referred to the practices of other investigating authorities, including the US practices wherein the US authorities conduct "expedited reviews" in certain situations and in particular when there is no or insufficient response from the foreign producers.
 - f) In the event of cessation of anti dumping duties, the landed price of imports from China PR are likely to be substantially lower than the selling price of the domestic industry, if the current anti dumping duties are not considered.
 - g) Exporters in China PR have built capacities far in excess of their domestic demand. This is established by significant exports from China PR to various other countries.

h) There is excess capacity available in China . Chinese producers with their surplus capacity can meet the entire demand in India in the event of revocation of anti-dumping duties, and thereby would be capturing the entire market share of the domestic industry by offering the subject goods at dumped prices.

(vi) There is clear likelihood of recurrence of dumping by the Chinese producers or exporters in the event of cessation of anti dumping duties.

(vii) The petitioner has provided evidence of the price at which the subject goods have been sold in the domestic Chinese market and claimed that even though normal value should be determined in accordance with para-7 of Annexure-I, nevertheless this clearly established that the selling price in China (and hence the normal value) is significantly high and the normal value determined by the petitioner was at the best lower than these selling prices.

(viii) Imports of the product under consideration declined significantly after restrictions on circumvention through third countries. Petitioner referred to actions taken by Directorate of Revenue Intelligence in this regard. Efforts of the domestic industry to curtail circumvention led to substantial decline in imports and the performance of the domestic industry improved.

(ix) There were no imports of the product under consideration in the current investigation period. However, imports have been once again reported in very significant volumes in the month of January (80 MT) and February 2011 (120 MT). Considering gross demand of 7,000 MT in India, this volume of imports must be considered significant. Further, these imports have been reported at extremely low prices, thus showing significant dumping. Petitioner assessed dumping margin and injury margin in respect of these imports and claimed that both the dumping margin and injury margin are quite significant.

(x) Petitioner claimed that anti dumping duty imposed on the product were circumvented heavily by exports of the product from third countries which were not even manufacturing the product. Import data showed imports of the product under consideration from Thailand, Russia, Indonesia, etc. Communications were sent to the Embassies/Missions of these countries in India seeking relevant information with regard to production of the product under consideration in these countries. There has been no reply from any of these countries. Further, communications were sent to Directorate of Valuation, Ministry of Finance and Department of Revenue Intelligence (DRI). Imports of the product substantially declined thereafter. Petitioner claimed that this clearly showed likelihood of dumping in the event of revocation of anti dumping duties.

(xi) Subsequent to the disclosure statement, the domestic industry has reiterated submissions made by them earlier during investigations. With regard to likely dumping margin, they have submitted that import of subject goods (120 MT) have come post POI at a price of US\$1.13 which indicates likely dumping margin of more than 45%. They have also enclosed working of dumping margin on the basis

of Chinese export price to other countries including India during Post POI which indicates dumping margin of approx 17%. In view of the above, they have requested the Authority to consider post POI exports to India from China PR to work out likely dumping margin during subject review.

VIEWS OF THE OTHER INTERESTED PARTIES

23. None of exporter from subject country filed any response with regard to the present investigation.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

24. The Authority has noted arguments made by the domestic industry on the methodology for determination of dumping and likelihood thereof. The Authority notes that this being a sunset review investigation, the Authority is required to examine continuation and likelihood of continuation or recurrence of dumping in the event of withdrawal of duty.

G. CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

25. The Authority sent copies of the questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). No response has been received from any of the producer/exporters from China PR and importers in India on dumping and dumping margin. The Designated Authority, therefore, has no option but to proceed on the basis of best information available on record under Rule 6(8) of AD Rules for non-cooperative exporter which provides that:-

"In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances".

NORMAL VALUE

26. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

The Authority notes that none of the Chinese producers have cooperated in the present investigation.

Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

27. The applicant has claimed that normal value should be determined on the basis of the above provisions. The Authority invited comments from all interested parties in accordance with para 7 and 8 of Annexure I.

28. The Authority notes that China has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. However, none of exporters/producers of the subject goods in China have cooperated with the Authority nor provided any information and evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to consider the following criteria as to whether-

- a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

29. The Authority notes that since none of the Chinese exporters have submitted questionnaire responses including the market economy questionnaire responses and sought to rebut the non-market economy presumption, the Authority is unable to consider whether one or more Chinese producers could be granted market economy status in the present case. The Authority is therefore constrained to proceed with para-7 of Annexure-I for determination of normal value in case of China.

30. The Authority notes that normal value can not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information from a producer in that country is not available to the Authority.

31. In view of the above and in the absence of cooperation from Chinese producers, the Authority has considered it appropriate to determine normal value on "any other basis" and has constructed normal value in China on the basis of best estimates of cost of production.

H. METHODOLOGY ADOPTED FOR CONSTRUCTING NORMAL VALUE IN CASE OF CHINA

32. The Authority has constructed normal value for the producers in China on the following basis –

- (a) Prices of major inputs have been considered on the basis of international prices.
- (b) Consumption of raw materials per unit of production have been considered on the basis of verified consumption norms of the domestic industry.
- (c) Conversion costs have been considered on the basis of information/data of efficient producer of the domestic industry.
- (d) Selling, general & administrative costs (including interest costs) have been taken on the basis of information/data of efficient producer of the domestic industry.
- (e) Profit has been added @ 5% of ex-factory cost excluding interest.

I. EXPORT PRICE:

33. Under section 9A (1) (b) export price means:

“export price”, in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is not export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

34. The Authority sent questionnaires to all known exporters/producers for the purpose of determination of export price. None of the exporters/producers from subject country filed any information.

35. The Authority notes that there are no known imports of the product concerned from China PR during the POI. Therefore, dumping margin in respect of POI exports cannot be determined taking into account the actual imports into India during the POI.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING –**DETERMINATION OF LIKELY HOOD OF CONTINUATION AND RECURRENCE OF DUMPING**

36. It is noted that the present sunset review investigation has been initiated vide notification dated 22nd June 2010 in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Thus, in a sunset review, the Authority is required to determine whether cessation of the existing duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.

37. It is noted from preceding paragraph that dumping margin cannot be determined for review POI as there are no exports of subject goods during the POI. In view of the above, there is no continuation of dumping of subject goods during the POI in view of no imports of subject goods during the POI.

DETERMINATION OF LIKELY HOOD OF RECURRENCE OF DUMPING**EXAMINATION BY AUTHORITY**

38. With regard to likelihood of recurrence of dumping, the Authority has relied upon the evidence available on record with regard to the price at which subject

goods have been exported from China PR to a number of other countries during and after the POI. The Authority has also examined export price of subject goods exported to India after the POI. It is noted that subject goods have been exported from China PR to other countries during the POI and a statement of exports downloaded from World Trade Atlas indicates that they have exported 7378 MT of subject goods at a total value of US\$ 10.07 million at an average price of US\$ 1.37 per Kg. In the absence of the any exports into India during the POI, the likely export price and dumping margin on a likely hood basis has been determined as mentioned below in the table.

	Normal value (US\$/Kg)	Export price(US\$/Kg)	Dumping margin(US\$/Kg)	Dumping margin %
(I) Considering exports to third countries				
All Producers and Exporters	1.50	1.37	0.14	10.08

39. For the period post the POI, the likely dumping margin based on the exports to other countries during Jan- Dec 2010 is approx 17%.

40. In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority, inter alia, considered the following parameters: -

- Likelihood of dumping considering the price at which goods have been exported to other countries during the POI and also during period immediately after the POI.
- Freely disposable present and potential capacities, prices prevailing in India, actual and potential volume of exports, export price from China PR to other countries.
- The quantity and rate at which the subject goods from China PR have come immediately after period of investigation.

41. On examination of these parameters, it is noted that

- None of the producers/exporters has responded in the present investigations. It has not been demonstrated that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of dumping and injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping. The Authority has proceeded on the basis of best information available/facts available.
- It is noted that the producers in China PR have exported the subject goods to other countries at significantly lower prices than constructed normal value determined for the POI. The likely hood of dumping margin based on the

export price of SFS to other countries during the POI and also post the POI is significant. It is also noted from the records that positive dumping margin has been determined on subject goods by Chinese Taipei against China PR and anti dumping duty has been imposed on China PR. It is also noted from the records submitted by the domestic industry that SFS is sold in China PR at a price of US\$1.6/Kg. Further, from the records available with the Authority, it is noted that subject goods have been exported to India after the POI at prices of US\$ 1.13/Kg which indicates significant dumping margin.

- c) It is noted from the material on record that the producers in China PR have significant freely disposable capacities. Not only that the producer has significant unutilized capacities, but also that the producers are having significant exports to various countries. The capacity, production and demand of the subject goods in China PR as submitted by the domestic industry are as under.

S.No.	Particulars	Unit	2006	2011
1	Chinese Capacity	MT	19600	24600
2	Production	MT	14700	21000
3	Unutilized Capacity (difference figure)	MT	4900	3600
4	Chinese Capacity	MT	19600	24000
5	Chinese demand	MT	9100	13000
6	Freely disposable capacity in China PR	MT	10500	11000
7	Indian Demand	MT	7004	7004
8	% of surplus capacity of Indian demand	%	150	166
9	Unutilized Capacity	MT	4900	3600
10	% of unutilized capacity of Indian demand	MT	69.96	51.4

- d) From the records available with the Authority, it is noted that there are significant unutilized capacities in China PR. Additionally, the Chinese producers are exporting to a number of countries and therefore possibilities of diverting third country exports to India are not ruled out.

CONCLUSIONS ON LIKELY HOOD OF RECURRENCE OF DUMPING

42. On the basis of the above analysis, it is concluded that there is a significant likely hood of recurrence of dumping of subject goods from China PR.

LIKELYHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

43. The Authority notes that this being a sunset review of antidumping duty already in force, continuation of material injury to the domestic industry, as well as likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from subject country.

VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

44. The domestic industry has submitted that:

(i) The Authority is not required to restrict to the requirements of Article 3 of the ADA and Annexure-II to the Rules in a sunset review case and causal link in review investigations is not required to be examined. WTO decision in the matter of OTCG has been referred to and relied upon.

(ii) In a situation where the Designated Authority holds that there is no continued injury to the Domestic Industry, petitioner requests the Designated Authority to examine likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of expiry of the anti dumping duty in force. Though the Domestic Industry is showing positive performance due to the duty in force, there is a great likelihood of the recurrence of injury to the Domestic industry.

(iii) Injury to the domestic industry is likely to recur which is established by significant positive price undercutting, significant freely disposal capacities with Foreign Producers in the subject country, price attractiveness of Indian market (higher prices in the Indian market vis-à-vis other third country market), dumping in third country markets by the producers in subject country. Analysis of the data/information in the present case suggests that injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties. In other words, both adverse volume injury and price injury to the domestic industry are likely in the event of revocation of anti dumping duties. Domestic Industry has quantified the potential volume injury and potential price injury that is likely in the event of expiry of the duty in force.

(iv) In the instant case, there is no volume effect on performance of the domestic industry as there is duty in force. However, there is likelihood of increase in imports in case of revocation of duty given (1) excess capacity in subject country, (2) price attractiveness of Indian market, (3) third country dumping.

(v) Present capacity with the Foreign Producers are already in excess of demand in the exporting country. Already capacities are unutilized. Further, fresh capacities are being added.

(vi) The influx of the exports of the subject country with respect to the subject goods and that too at dumped prices would force or compel the domestic industry to reduce the selling price of the subject good in the Indian domestic market, as an alternative to loss of sales.

(vii) Thus, it has been submitted that in the event of expiry of anti dumping duty, the domestic industry would have to choose between declining sales volumes and reduction in prices. Should the domestic industry prefer to match the prices, the price declines would be too significant.

(viii) Subsequent to the issuance of disclosure statement, the domestic industry has drawn the attention of the Authority towards their allegation of circumvention of anti dumping duties through countries not producing and countries producing SFS. They have again highlighted the attention of the authority with regard to imposition of significant anti dumping duties by Chinese Taipei on imports of SFS from China PR. They have also added that in view of the significant anti dumping duty, the Chinese producers would have to look for alternate markets. They have further added that significant imports prior to POI and post POI imports of subject goods from China PR at very low at dump prices, establish likelihood of dumping injury. It is also been added that the likely landed prices of imports are below the selling price of domestic industry and expiry of anti dumping duties would lead to significant price under cutting in the domestic market. Further, the likely landed prices of imports from China to third countries are below the non-injurious price of domestic industry which signify significant price under selling. They have added that the domestic industry suffered injury during the beginning of injury period in the presence of dumped imports in the market and performance of domestic industry improved as the dumped imports declined. The existence of injury in the presence of dumping and no injury in the absence of dumping establish likelihood of dumping and injury in the event of expiry of anti dumping duties. With regards to the quantum and form of duty, the domestic industry has submitted that the instant case being the sunset review investigation, the quantum of duty should remain same as has been recommended by the Designated Authority in the original investigation. On the quantum and form of duty, they have submitted the following:

- a) The case of domestic industry for extension of anti dumping duties is based on likelihood of dumping and injury and therefore the same quantum of anti dumping duty should be extended;
- b) Since there are no exports to India in the current dumping POI, either the quantum of anti dumping duty should be based on imports prior to or post dumping POI, or the Authority should extend the current anti dumping duties;
- c) While there are exports to third countries, these can be used only to ascertain whether the domestic industry is likely to suffer dumping and consequent injury in the event of cessation of anti dumping duties. These cannot be used to determine the quantum of anti dumping duties. Amongst other reasons, these are to those countries where there is no domestic production and price difference between exports to India and third countries clearly establishes that the export price to third countries does not establishes the likely dumping margin and injury margin in the event of cessation of anti dumping duties;
- d) The Rules provide for a determination of whether the anti dumping duties should be extended further. This implies a decision on whether or not to extend the duties further. While the Designated Authority in practice has also utilized this opportunity to modify the quantum of anti dumping duties, such opportunity is not available where the case is based on likelihood of dumping and injury.
- e) The practice being followed by third countries such as Canada, US and Europe is to decide whether or not to extend the anti dumping duties. These

- countries do not at all alter the quantum of anti dumping duties even if there are very significant imports in the POI and the dumping margin & injury margin (EC) is quite lower than existing anti dumping duties.
- f) There is past precedence available wherein the Designated Authority has extended the same quantum of duty as has been recommended in their respective original investigations in spite of dumping margin in review cases being lower than what was determined in the original investigations. Some such known cases including a case from EU are as follows:
- (i) Sunset review investigations in the matter relating to imports of Hexa Methylene Tetramine(Hexamine) originating in or exported from the Islamic Republic of Iran
 - (ii) Sunset review antidumping investigation into alleged dumping of Phenol originating in or exported from Singapore, South Africa and European Union.
 - (iii) Sunset Review Investigation against Imports of White Cement originating in and exported from UAE and Iran
 - (iv) COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1242/2010 of 20 December 2010 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of synthetic fibre ropes originating in India following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
- g) Given above, the domestic industry has requested the Authority to keep the quantum of anti dumping duty as same as has been determined during the original investigations.

VIEWS OF THE EXPORTER/ IMPORTER/OTHER INTERESTED PARTIES.

45. None of the other interested parties have advanced any arguments

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

46. The Authority has taken note of various arguments raised by the domestic industry with regard to the material injury to the domestic industry.

47. The Authority has examined the submissions made by the domestic industry regarding the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in case of expiry of duty. It is noted that the present investigation has been initiated in terms of Section 9A(5) of Customs Tariff Act which requires the Authority to determine whether the duty is required to be continued for a further period of five years and to examine the degree and extent of likely dumping and injury and the need for continuation or revocation of duty based on the information provided and arguments raised by various interested parties during the course of the investigation. For the purpose of assessing current injury or continuation of injury

during the injury period, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the domestic industry.

K. ASSESSMENT OF DEMAND AND MARKET SHARE

48 For the purpose of determining the demand and market share, the Authority has considered sales of the domestic industry and imports from various sources. The demand of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the Indian Producers and known imports from various countries. The demand so assessed is shown in the following table.

		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Subject Country-China PR	MT	20	200	20	0
Trend	Index	100	1000	100	0
Other Countries	MT	560	198	80	2
Sales of Domestic Industry	MT	3507	3390	3422	4597
Trend	Index	100	97	98	131
Sales of other producers	MT	1690	1520	1835	2405
Total Demand-excluding captive	MT	5777	5308	5357	7004
Trend	Index	100	92	93	121
Market Share in Demand					
Subject Country-China	%	0%	4%	0%	0%
Other Countries	%	10%	4%	1%	0%
Sales of Domestic Industry	%	61%	64%	64%	66%
Sales of other producers	%	29%	29%	34%	34%
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

49 It is noted that the demand of the subject goods has shown a positive trend during the injury period. The sales of the domestic industry have improved during the injury period.

VOLUME EFFECT

50. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there is significant actual or potential increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

“While examining the volume of dumped imports the said Authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”

51. ACTUAL VOLUME OF IMPORTS DURING THE PERIOD HAVE BEEN AS UNDER -

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Imports volume					
China PR	MT	20	200	20	-
Other Countries	MT	560	198	80	2
Total imports	MT				
Market share in imports					
China PR	%	3.45	50.25	20.00	-
Other Countries	%	96.55	49.75	80.00	100.00
Market share in Demand					
China PR	%	0.35	3.77	0.37	0.00
Other Countries	%	9.69	3.73	1.49	0.02

52. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown a positive trend and increased significantly in the period of investigation as compared to the base year. The Authority notes that as compared to base year where the demand has increased by 21%, the sales of domestic industry have increased by 31%. On the other hand, no imports from the subject country have been recorded during the POI.

PRICE EFFECT

53. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows“

“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”

PRICE SUPPRESSION AND DEPRESSION DURING THE INJURY PERIOD

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Cost of sales	Rs/Kg	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	92	86	86
Net sales realization	Rs/Kg	****	****	****	****

Trend	Indexed	100	98	116	118
-------	---------	-----	----	-----	-----

54. Price depression exists when the industry's prices are lower than the level of the previous period. Price suppression occurs when dumping prevents price increases that would otherwise take place due to increase in costs. The cost and price structure of the domestic industry show that the cost has decreased by about 22% over the base year whereas the prices of domestic industry have increased by 18%. Hence, the price suppression/ depression are missing as the cost of sales has declined whereas the selling prices have increased during the POI as compared to the base year.

55 In a sunset review investigation, it is required to be examined whether there was a significant adverse price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether there is likelihood of significant adverse price effect in case of expiry of anti dumping duty.

56 The Authority further determined whether the domestic industry is likely to face price underselling in the event of expiry of anti dumping duties. For the purpose, the Authority has considered likely export prices from China PR as prices of subject goods from China PR to other countries and also the price at which subject goods have been imported into India from China PR immediately after the review POI and compared the same with the selling price of the domestic industry. The Authority notes that the likely price from China PR is significantly lower than the selling price of the domestic industry.

OTHER ECONOMIC PARAMETERS RELATING TO THE DOMESTIC INDUSTRY

57. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an object examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down as follows“

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

PRODUCTION, CAPACITY AND CAPACITY UTILIZATION, SALES

58. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below.

Particulars	Unit	2006-	2007-	2008-	2009-
-------------	------	-------	-------	-------	-------

		07	08	09	10
Installed capacity	Mt	8,000	8,000	10,500	10,500
Trend	Indexed	100	100	131	131
Production	Mt	6,273	8,020	7,876	9,518
Trend	Indexed	100	128	126	152
Capacity utilization	%	78%	100%	75%	91%
Trend	Indexed	100	128	96	116
Captive Transfer	MT	149	187	226	319
Trend	Indexed	100	126	152	215
Domestic sales	Mt	3,507	3,390	3,422	4,597
Trend	Indexed	100	97	98	131
Demand excluding captive consumption	Mt	5776	5308	5357	7004
Trend	Indexed	100	92	93	121
Sales as % of demand	Mt	61%	64%	64%	66%
Trend	Indexed	100	105	105	108

59. The Authority notes that the production and capacity utilization of the domestic industry have gone up during the POI over the injury period.

60. The domestic sales of the domestic industry of the subject goods have gone up in absolute terms and also in relation to demand/consumption of the product in India.

PROFITS, RETURN ON INVESTMENT AND CASH FLOW

61. Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as under:

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Profit before tax	Rs/Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	(100)	(66)	21	33
Profit before interest and tax	Rs/Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	(100)	(64)	27	39
Return on capital employed (NFA basis)	%	****	****	****	****

Trend	Indexed	(100)	(70)	23	24
Cash profit	Rs/Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	(100)	(66)	27	42

62. The above data shows that the profitability has significantly improved in POI as compared to the base year.

EMPLOYMENT AND WAGES

63. The Authority notes that the constituent of the domestic industry is a multi product company; therefore, there may not be direct effect of dumping on employment levels of the domestic industry. Status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Employment	Nos	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	105	116	123
Wages	Rs/Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	95	111	167

64. The Authority notes from the above that employment level of the domestic industry has shown improvement. Further, the level of wages has also increased during POI as compared to base year.

PRODUCTIVITY

65. The productivity of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Productivity per employee	Mt	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	121	108	124
Productivity per day	Mt	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	128	126	152

The Authority notes productivity has improved in tandem with production.

INVENTORIES

66. The Designated Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Average stock	MT	247	179	88	32
Trend	Indexed	100	72	36	13
Average stock in terms of No. of days sales	No. of days	26	19	9	3
Trend	Indexed	100	75	37	10

Based on the above, Authority notes that the inventory levels of the domestic industry have declined in the POI as compared to base year.

ABILITY TO RAISE CAPITAL INVESTMENT

67. It is noted that the ability to raise capital investment of the domestic industry has not been adversely affected given the anti dumping duty in force. The domestic industry has made fresh investments in products under consideration, given the imposition of anti-dumping duties and resultant check on dumping.

GROWTH

68. The Authority notes that Growth of the domestic industry during the POI as compared to the base year in terms of all the economic parameters like production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, cash profits and return on capital employed has been positive.

MAGNITUDE OF DUMPING

69. It is noted that there is no dumping of subject goods during the POI as there are no imports from subject countries.

FACTORS AFFECTING DOMESTIC PRICES

70. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might affecting the prices in the domestic market. It is noted with the anti dumping duty in place, there are no external factors affecting the prices of the domestic industry during the injury period of this review investigation.

MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

71. As there is no export price of the subject goods from the subject country during the POI, no injury margin has been determined during the POI.

CONCLUSION ON CONTINUATION OR CURRENT INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY

72. It is noted that growth of the domestic industry during the POI as compared to the base year in terms of all the economic parameters like production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, cash profits and return on capital employed has been positive. There is thus no adverse effect on the volume as well as price parameters of the domestic industry during the POI. In view of the above analysis of various injury parameters during injury period, it is noted that there is no continuation of injury to domestic industry during the POI.

OTHER KNOWN FACTORS AND CAUSAL LINK

73. The Authority has examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

VOLUME AND PRICES OF IMPORTS FROM OTHER SOURCES

74. It is noted that the imports of the product under consideration from other countries are almost negligible and are nil during the POI.

CONTRACTION IN DEMAND AND / OR CHANGE IN PATTERN OF CONSUMPTION

75.. It is noted that the demand of the subject goods has not registered negative growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to injury to the domestic industry.

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Demand	MT	5777	5308	5357	7004

76. No evidence of change in consumption pattern has come to the notice of the Authority.

TRADE RESTRICTIVE PRACTICES OF AND COMPETITION BETWEEN THE FOREIGN AND DOMESTIC PRODUCERS

77. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The subject goods produced by the domestic producer compete among one another and at the same time compete with the landed price of the subject goods.

DEVELOPMENTS IN TECHNOLOGY

78. It is noted that the technology for production of the product has neither undergone any material change nor is likely to change in future. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury. The petitioner is producing the product under consideration for the past several years. The technology adopted by domestic industry is comparable to the technology adopted by other players world-over. In fact, it has been submitted that technology for production is fairly matured, established and standardized, with little technological innovations and developments.

PRODUCTIVITY OF THE DOMESTIC INDUSTRY

79. It is noted that productivity of the domestic industry has shown a growth. Possible decline in productivity does not appear to be a cause of injury to the domestic industry.

LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY

Examination by Authority

80. In addition to the examination of continued injury, likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty in force has also been examined by the Authority on the basis of information and evidence presented by various interested parties during the course of the investigations. The Authority has also examined the likelihood of recurrence considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

- (a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- (b) *Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- (c) *Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,*

(d) *Inventories of the article being investigated.*

81. The domestic industry has submitted that the requirement under sunset review is to examine whether expiry of anti dumping duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry. It is noted that none of the exporters/producers from any of the subject country as well as any of the Indian importers/consumers have responded in this review investigation. The domestic industry has provided information regarding capacity, production and demand of subject goods of the exporting country based on best available information with them. Therefore, all such factors brought to the notice of the Authority, have been examined, to find if there is a likelihood of recurrence of injury in the event of expiry of the duty.

82. For examining the likely hood of recurrence of injury in the absence of any imports of subject goods from China PR during the POI, the Authority has taken into account exports of subject goods to other countries during the POI and also post POI from China PR. The Authority has also examined the landed prices of subject goods into India from China PR post POI. On the basis of examination of landed prices (taking into account prices to all other countries during POI and post POI) and non injurious price determined for the domestic industry during the same period, it is noted that the landed value of imports from the subject country without the antidumping duty were below the non injurious price determined for the domestic industry. The Authority has also examined the price at which the subject goods have been imported into India immediately after the POI and notes that there is significant price undercutting on account of imports of subject goods from China PR just after the POI and margin of price underselling is also significant.

83. In order to assess the likely effect of the expiry of measures in force, it has been submitted that the subject country have the potential to raise their production and export volumes. Further, it is likely that in absence of measures, the producer from subject country would adopt a policy of dumped prices, which could cause injury to the domestic industry, which has recovered and improvement has been shown due to the anti-dumping duty in place against dumped imports from subject country. The domestic industry has submitted various evidence regarding the likely volume of imports from subject country in a situation of expiry of duty and the likely prices at which such imports would be made and likely impact on the domestic industry due to such imports.

84. From the records available with the Authority, it is noted that upon the expiry of anti dumping duty on subject goods from China PR, exporters from subject country are likely to export the subject goods at dumped prices in the Indian market and producers in the subject country are likely to resort to higher volume of dumped exports of subject goods in the Indian market due to excess capacities in subject country and surplus available with them.

85. The Authority has examined the likely price effects of the subject goods imports into India from China PR in the event of cessation of anti dumping duty and notes that factors such as, the level of import prices of subject goods from

subject country to third countries, surplus/freely disposable capacities available with the exporting countries suggest that expiry of anti dumping duty on subject goods from China PR would likely to result in significant increase in volume of dumped imports from subject country. The volume of dumped imports is likely to increase further, upon the cessation of present anti dumping duties. Thus, it is noted that in the event of cessation of anti dumping duty, the likely hood of subject goods being imported at dumped prices and causing adverse price impact to domestic industry is very strong.

86. It is also noted that Chinese Taipei has already imposed anti dumping duty on SFS from China PR during 2010 and a copy of the same has been placed by domestic industry in the written submission following public hearing. The duty ranges from 14% to 28%. It is noted that imposition of anti dumping duty by Chinese Taipei could result into loss of market for Chinese producers of subject goods from China PR and there could be a likely hood of injury resulting from higher volume of imports of subject goods at dumped prices after the POI.

CONCLUSION ON LIKELY HOOD OF RECURRENCE OF INJURY

87. From the above analysis as mentioned in the preceding paragraphs, it is noted that upon the expiry of anti dumping duty on subject goods from subject country, there is a strong likely hood of recurrence of dumping of subject goods from China PR causing an adverse volume and price effect and there is strong possibility that domestic industry would be adversely impacted by large volume of dumped imports.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

88. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

89. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

CONCLUSIONS:

90. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of recurrence of dumping and consequent injury, the Authority concludes that:

- (i) The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices if the anti-dumping duties in force ceases to operate.
- (ii) The situation of domestic industry is likely to deteriorate if the existing anti dumping duties are allowed to cease.
- (iii) The deterioration in the performance of the domestic industry is likely to be because of dumped imports from the subject countries.
- (iv) Thus the anti-dumping duties are required to be extended.

L. RECOMMENDATIONS:

91. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury, if the existing anti dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended in respect of imports from China PR.

92. Having examined the likelihood of dumping and injury to be imminent in case of expiry of the current measure in place, the Authority recommends continued imposition of Anti-Dumping Duty in place as recommended by the Authority vide Final Findings Notification No. 14/25/2004-DGAD dated 25.01.2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I and notified by the Central Government vide Notification No. 23/2006 -Custom dated 06.03.2006.

93. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority